भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3471
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

कोयम्बटूर/मदुरै में आईआईटी की स्थापना

†3471.डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु के दक्षिणी भाग को लाभ पहुंचाने के लिए कोयम्बटूर या मदुरै में नए आईआईटी स्थापित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): वर्तमान में देश में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित और कार्यरत हैं। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (आईएनआई) आईआईटी मद्रास पहले ही स्थापित किया जा चुका है। आईआईटी मद्रास के अलावा, राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), तिरुचिरापल्ली और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिज़ाइन एवं विनिर्माण संस्थान कांचीपुरम (आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम) जैसे अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थान भी हैं। ये प्रतिष्ठित संस्थान तकनीकी शिक्षा, बुनियादी और अनुप्रयुक्त दोनों क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और उद्योग को परामर्श सेवाओं में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में मौजूदा शैक्षणिक संस्थाओं की बुनियादी अवसंरचनाओं, प्रशासन और संसाधनों में सुधार करके उन्हें मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में भी शिक्षा और अनुसंधान में उच्चतम मानक स्थापित करने हेतु मॉडल सार्वजनिक संस्थान के रूप में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना की भी सिफारिश की गई है। आईआईटी मद्रास एनईपी 2020 के विजन को साकार कर रहा है और विज्ञान और इंजीनियरिंग को प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान के साथ एकीकृत करते हुए समग्र, बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लोचशील शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इसके अलावा, आईआईटी मद्रास शिक्षा, अवसंरचना विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और तकनीकी नवाचार का सहयोग करने हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार के कई विभागों और एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। संस्थान ने शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, जल, शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं।